a result, these
n forced to cut
to eight hours
vailability. Most
s are in smaller
ages, officials

al said that this
rtage of coal,
seen only dur-
ons, has come
ng caused by a
es. "The situa-
get worse with
ods, sparking a
wer crisis in the

ock is critical
ster (Bhagwant
eady taken up
Coal and Power
crease the coal
e the onset of
eason, in which
k to the level of
id Baldev Singh
jab State Power
mited.
Maharashtra's
, said they were
g coal invento-
thermal power
e optimum gen-
; that state was
ectricity from
ower producers
20 lakh metric

orporation Ltd
man M Devraj
e that thermal
t able to main-
ocks as per the
he claimed, was
normal power
n the state.
re also making
o maintain the
s per the norms
al to the plants
avoid possible
e often caused
ransported by

*m state bureaus)*

were axed.

The move came days after the Chhattisgarh government granted the final approval for non-forestry use of forest land in the Parsa coal mining project area.

According to villagers, they learnt about the deforestation exercise early in the morning and rushed to the spot to register their objection.

On April 6, the state government had given the final approval for non-forestry use of 841.538 hectares of forest land for the Parsa coal mine spread across Surguja and Surajpur districts in northern part of the state.

The mine has been allotted to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd (RRVUNL).

"As many as 300 trees were felled in Janardanpur village (Surajpur district) under the Ramanujnagar forest range for the Parsa coal mine project. After the objection by local villagers, the work was stopped," a local forest official said.

"Around 1,590 trees are to be cut in this area for the project. Further action in this direction will be taken after getting directives from senior officials," he added.

On getting information about the deforestation work in Janardanpur which is close to Salhi village (Surguja district), residents of project-affected villages reached there, said Ramlal Kariyam, a resident of Salhi.

Over 50 police personnel were deployed to facilitate the deforestation work, he added. "The residents of Salhi, Fatehpur and Hariharpur villages have been protesting against the project for a long time. We have even demanded a probe into forged gram sabha documents based on which clearances have been given for the project," he said.


| | | |
|---|---|---|
| b) | Pre Bid Conference | 5th May 2022 at 11:00 AM<br>Google Meet joining info Video call link:<br>**https://meet.google.com/uij-pfax-bgr** |
| c) | bid submission end date and time | 18 May 2022 upto 06:00 PM |
| d) | Technical bid opening date and time | 19 May 2022 at 11:00 AM |
| e) | Financial bid opening date | To be decided after evaluation of Technical Bid |
| f) | Venue of opening Technical & Financial – bid is UPNEDA Head Office | |

As such the hard copies of the tender document is not required to be sent, however the Demand Draft of Bid Processing Fee Rs. 4000.00 +GST Rs. 720.00 total Rs. 4720.00 and Earnest Money Rs. 20500.00 as Bank Guarantee or Demand Draft and other relevant documents (as detailed in the bid document), should reach UPNEDA's head office latest by **19 May 2022 upto 10:00 AM.** The Demand draft of any nationalized or Scheduled bank should be in favour of Director UPNEDA.

All updation/information about above tender will be publish on UPNEDA **website www.upneda.org.in and/or E-Tender website** www.etender.up.nic.in.

The Director, UPNEDA reserves the right to reject any/all offer without assigning any reason thereof. The decision of the Director UPNEDA shall be final and binding.

**DIRECTOR**
**UPNEDA**


मुख्यालय

## उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
Web: www.ueppcb.uk.gov.in E-mail: msukpcb@yahoo.com Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

# पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

**श्री कैलाश चंद जोशी, निवासी–ग्राम व पो0 बिलोना, बिलोनासेरा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम महतगांव, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल–3.77 है0, उत्पादन–14,200 टन प्रतिवर्ष क्षमता)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्रावधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

**श्री कैलाश चंद जोशी, निवासी–ग्राम व पो0 बिलोना, बिलोनासेरा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम महतगांव, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल–3.77 है0, उत्पादन–14,200 टन प्रतिवर्ष क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 02.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड–19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।**

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

**सदस्य सचिव**
**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

H. Times. 28/4/2022